facilities from some public sector banks and the exposure of these banks is presently estimated to be in the region of Rs. 12 crores.

(c) Consequent upon a petition filed by the Reserve Bank of India under section 45 MC of the Reserve Bank of India Act, the Delhi High Court has appointed a Provisional Official Liquidator. The Liquidator has initiated steps to crystallize the assets and liabilities of the company. He is being assisted by the officials of RBI, CBI and some public sector banks in this regard. The issue of settlement of claims of creditors, including banks, is now subjudice and would proceed as per the provisions of law and the directions of the Delhi High Court.

प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी निर्देश

694. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार देश में बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किए जाने के पुराने निर्देशों में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो दिये गये नवीन निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए लक्ष्य में निवल बैंक ऋण के 33 1/3 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। और यह मार्च, 1985 तक प्राप्त किया जाना था। तब से ही निर्धारित लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राथमिकता क्षेत्र को निदेशित ऋण देने का मूल्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खण्ड के अन्तर्गत कमजोर वर्गों और छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करना है और इसीलिए बैंकों से कहा गया है कि वे इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की अनुपालना करें। तथापि, निवेश आदि के मूल्य में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

(i) लघु उद्योगों की परिभाषा में समय-समय पर संशोधन किया गया है और वर्तमान में इसमें वे ईकाइयां सम्मिलित हैं जिनकी संयंत्र और मशीन में निवेशों की मूल लागत 60 लाख रुपए (अनुषंगी और निर्यातोन्मुख ईकाइयों के लिए 75 लाख रुपए) से अधिक नहीं है।

(ii) प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत निजी खुदरा व्यापारियों (उनके अलावा जो अनिवार्य वस्तु वस्तुओं, उचित दर की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी स्टोर से संबंधित हैं) को अग्रिमों के लिए सीमा मार्च, 1994 में 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दी है।

(iii) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत छोटे कारोबार की परिभाषा की मार्च, 1994 मे पुनरीक्षा की गई है जिसमें कि उन ईकाइयों (जो मुख्यत: व्यावसायिक सेवा से भिन्न कोई अन्य सेवा प्रदान कराने के प्रयोजन से स्थापित की गई हों) को सम्मिलित किया जा सके तथा जिनकी कारोबार के प्रयोजन के लिए मूल प्रयोग किए गए उपस्कर की लागत 10 लाख रुपए से अधिक न हो और जिसकी कार्यशील पूंजी की सीमा 5 लाख रुपए तक हो (जो क्रमश: 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए से संशोधित की गई है)

(iv) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्तियों को अग्रिमों के लिए सीमा मई, 1994 में (2 लाख रुपए से) 5 लाख रुपए तक बढाई गई है जिसमें से 1 लाख रुपए से अधिक कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यसवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चिकित्सकों जो अपनी प्रेक्टिस अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, के लिए तदनुरूपी सीमा क्रमश: 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है।

(v) प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, आवास वित्त के लिए सीमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त, दोनों के संबंध में फरवरी, 1997 में प्रति आवास ईकाई 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है।

विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक सहायता

695. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा भारत को वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न रूपों में

आर्थिक सहायता देने का वचन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों के नाम क्या हैं तथा इन संस्थानों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि दी जाएगी तथा यह राशि किस रूप में दी जाएगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1997-98 के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता वर्ष 1996-97 में दी गयी वित्तीय सहायता की तुलना में कम है; यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1996-97 के लिए भारत विकास मंच की बैठक, 1996 में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताओं द्वारा की गई सरकारी विकास सहायता की कुल वचनबद्धता 6.66 बिलियन अमरीकी डालर थी। वर्ष 1997-98 के लिए भारत विकास मंच की बैठक, 1997 में की गई सरकारी विकास सहायता कुल वचनबद्धता 6.74 बिलियन अमरीकी डालर है, जो कि पिछले वर्ष से कुछ अधिक है।

Newsitem Regarding FEMA

696. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the Statesman, dated 24th May, 1997 captioned "Weak FEMA may aid white collar crime";

(b) if so, whether the proposed FEMA is strong enough to deal with various financial crimes particularly those relating to the evasion of customs and excise duties; and

(c) whether Government are aware that Section 8, 9 and 16 of FERA are not replicated in FEMA, consequently leading to dropping of proceedings in more than 3000 cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Government proposes to repeal FERA 1973 and replace it by Foreign Exchange Management Act. (FEMA), the draft of which is under consideration of the Government.

RBI circular regarding 'at par' facilities to companies

697. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI BRATIN SENGUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether RBI in 1994 issued a circular to banks with regard to 'at par' facilities granted to compaines for payment of dividend warrants and refund orders;

(b) if so, how many banks have followed the said circular, and

(c) reasons for others not following the said circular?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Reserve Bank of India (RBI) had not issued any circular in 1994 to banks with regard to 'at par' facilities. RBI had only issued a secret Caution Advice dated 7.6.1994 addressed to chief executive officers of all commercial banks on the basis of a fraud reported in 1994 where a bank appointed as refund banker in connection with public issue made by two companies had granted 'at par' facilities & the companies had issued refund orders far in excess of the amount agreed to or deposited with the bank with the result that the account became heavily overdrawn. RBI's Caution Advice described the *modus-Operandi* and cautioned banks against the companies mentioned therein. It did not contain the detailed instructions with regard to 'at par' facility. RBI have stated that with regard to caution advices, RBI calls for acknowledgements and does not call for compliance.

(b) and (c) Dot not arise.

Proposal to regulate tree plantation companies

698. SHRI BRATIN SENGUPTA:
PROF. RAM KAPSE: